

पांच साल से कोयला उत्पादन, फिर भी हक के लिए सड़क पर ग्रामीण, टीएचडीसी खदान में चार घंटे ठप रहा परिवहन पीड़ित परिवारों का आरोप,मुआवजा और पुनर्वास अब भी अधूरा

महिलाएं लाठी-डंडे लेकर वाहनों के सामने डटीं, विस्थापितो ने कंपनी प्रबंधन पर लगाया आरोप

सिंगरौली

खदान से कोयला निकलता रहा, वाहनों की कतारें दौड़ती रहीं, लेकिन जिन ग्रामीणों की जमीन और घर इस परियोजना से प्रभावित हुएए उनके मुआवजे और पुनर्वास का सवाल अब भी जवाब मांग रहा है। सोमवार को टीएचडीसी कोल माइंस में इसी नाराजगी ने उग्र प्रदर्शन का रूप ले लिया। अपने अधिकारों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कोयला परिवहन रोक दिया। महिलाएं लाठी-डंडे लेकर वाहनों के सामने खड़ी हो गईं। देखते ही देखते सैकड़ों कोयला वाहनों के पहिए धम गए और चार घंटे से अधिक समय तक परिवहन प्रभावित रहा। यह प्रदर्शन केवल मुआवजे की मांग नहीं बल्कि वर्षों से लंबित समस्याओं को लेकर



ग्रामीणों की नाराजगी का संकेत है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि परियोजना में लंबे समय से खनन गतिविधियां जारी हैं लेकिन उन्हें अपने हक के लिए बार-बार आवाज उठानी पड़ रही है। सवाल सीधा है,जब कोयले का उत्पादन और परिवहन लगातार जारी रह सकता है, तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे का समाधान समय पर क्यों नहीं हो सकता? प्रभावित ग्रामीण हीरामती सिंह ने आरोप लगाया कि खदान में होने वाली ब्लास्टिंग से उनके घर में दरारें आ रही हैं और प्रदूषण की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। संपत्तियां देवी ने दावा किया कि आंदोलन करने पर पुलिस



बुलाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। वहीं सुंदर काली ने उचित मुआवजे के साथ विस्थापन की स्थिति में दूसरी जगह सम्मानजनक ढंग से बसाए जाने की मांग उठाई। ये आरोप ग्रामीणों के हैं, जिन पर संबंधित पक्ष का स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है।

प्रबंधन का दावा, अब समय सीमा की परीक्षा

टीएचडीसी के उप प्रबंधक सीके गोस्वामी के मुताबिक, अधिकांश ग्रामीणों को विस्थापन का लाभ दिया जा चुका है, जबकि कुछ मामले बाकी हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी ने जिला

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित

त्योहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने व वेदखली के आदेशो का पालन करने के निर्देश

सिंगरौली। कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, लंबित शिकायतों के निराकरण, विकास कार्यों की प्रगति, छात्रावासों की व्यवस्थाओं तथा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें। संबंधित थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने वेदखली एवं विवादित रास्तों से संबंधित आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने तथा रास्तों पर अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टों के पंजीयन की कार्रवाई निरंतर जारी रखने और सभी पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार निशुल्क पट्टा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों की व्यवस्थाओं का औखक



निरीक्षण कराने के लिए अधिकारियों को संस्थान आवंटित कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने आवंटित छात्रावासों एवं आश्रमों में मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था तथा अधोसंरचना की स्थिति का परीक्षण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कन्या शिक्षा परिसर बरगवा में पंप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को दिए।

मॉडल रोड के निर्माण कार्य में लाएं तेजी

छात्रावासों में डीएमएफ मद से उपलब्ध कराई गई रोटी मेकर मशीनों का भौतिक स्थापन कराने के लिए जांच दल गठित करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को मॉडल रोड निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा

योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित समय.सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को मेडिकल कॉलेज सड़क निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने चितरंगी विकासखंड के बरदी में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिएए ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणजन शिविर की जानकारी प्राप्त कर योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ ले सकें।

विंध्याचल में साइबर खतरों से बचाव पर जागरूकता सत्र का आयोजन



सिंगरौली। एनटीपीसी विंध्याचल के क्षेत्रीय ज्ञानार्जन संस्थान आरएलआई द्वारा सतर्कता विभाग के सहयोग से सतर्कता जागरूकता माह के अंतर्गत 12 अक्टूबर को साइबर सुरक्षा विषय पर अर्द्धदिवसीय जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में एमएकेपी सिंह, पूर्व

एनटीपीसी की सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति में साइबर स्वच्छता एवं डिजिटल सतर्कता को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी एवं डिजिटल माध्यमों से होने वाले विभिन्न खतरों के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया। साथ ही कर्मचारियों को अपने सहकर्मियों एवं संचिदा श्रमिकों तक साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि डिजिटल सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता एवं सामूहिक सतर्कता से जुड़ी साझा जिम्मेदारी है।

देवसर में कॉलेज जाने वाली सड़क पर गंदे पानी और कचरे से छात्र परेशान हजारों विद्यार्थियों सहित रोजाना 2 से 3 हजार लोगों का होता है आवागमन

सिंगरौली। शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ही जब गंदे पानी और कचरे से घिरा हो, तो विद्यार्थियों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। देवसर में राष्ट्रीय राजमार्ग से शासकीय महाविद्यालय की ओर जाने वाली पीसीसी सड़क पर गंदा पानी बहने और बाजार का कचरा जमा होने से छात्र-छात्राओं सहित स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बंदू और गंदगी के बीच आवागमन करना लोगों की मजबूरी बन गया है। जानकारी के अनुसार इस मार्ग से शासकीय महाविद्यालय



के 1000 से अधिक छात्र-छात्राएं प्रतिदिन गुजरते हैं। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों और अन्य लोगों को मिलाकर रोजाना करीब 2 से 3 हजार लोगों का आवागमन होता है।

कचरा जमा होने से विद्यार्थियों को कॉलेज पहुंचने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गंध के कारण इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है। यह समस्या केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजाना इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले ग्रामीणों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस समस्या को पहले भी नेताओं और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाया जा चुका है। इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हजारों लोगों

के रोजाना उपयोग में आने वाले इस मार्ग की बदहाली दूर करने के लिए जिम्मेदार विभाग कब ठोस कदम उठाएंगे।

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए और बाजार क्षेत्र में जमा कचरे की नियमित सफाई कराई जाए, ताकि विद्यार्थियों को कॉलेज आने.जाने में परेशानी न हो और ग्रामीणों को भी राहत मिल सके।

एनटीपीसी सिंगरौली ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जन-जागरूकता का प्रसार

सिंगरौली। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा 11 अक्टूबर को शक्तिनगर स्थित संडे मार्केट में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस जन-जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को स्वच्छता, साफ-सफाई तथा कचरे के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रभावशाली एवं रोचक तरीके से यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था



की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने, कचरे का उचित निस्तारण करने तथा दैनिक जीवन में स्वच्छता संबंधी अच्छी

आदतों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही लोगों को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने और स्वच्छता के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संडे मार्केट के दुकानदारों, ग्राहकों एवं अन्य लोगों के बीच कपड़े के थैलों का विवरण भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था। इसके माध्यम से दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार उपभोग की आदतों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।

सेवानिवृत्ति से पहले डीके सिंह को मिला कार्यपालन यंत्री का प्रभार, आयुक्त ने जारी किया आदेश

सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली में सहायक यंत्री डीके सिंह को सेवानिवृत्ति से पहले कार्यपालन यंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नगर निगम आयुक्त द्वारा 12 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार डीके सिंह आगामी 31 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उन्होंने नगर निगम में 37 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि डीके सिंह को बांछित समय पर पदोन्नति नहीं मिल पाने के कारण कार्यपालन यंत्री बनने का अवसर नहीं मिल सका।

खनुआ तिराहा स्थित किराना स्टोर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका आग लगने का कारण अज्ञात,पतासाजी में जुटी पुलिस

सिंगरौली। सरई थाना अंतर्गत खनुआ तिराहा स्थित लकुरदीन किराना स्टोर के गोदाम में राखवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब एक बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गोदाम में आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, खनुआ चौराहा स्थित लकुरदीन किराना स्टोर के गोदाम में देर रात अचानक आग की लपटें उठने लगीं। रात का समय होने के कारण घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गोदाम में रखे किराना सामान में आग फैलने से बड़े नुकसान की आशंका है। घटना के

बाद आग लगने के कारणों और नुकसान के वास्तविक आकलन को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। आग कैसे लगी, गोदाम में कितना सामान जलकर नष्ट हुआ और आग पर काबू पाने के लिए क्या कार्रवाई की गई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

नशामुक्त युवा, स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का संदेश लेकर उतरा विहिप व बजरंग दल

शासकीय आईटीआई कॉलेज पंचौर में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक

सिंगरौली। युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखकर स्वस्थ, संस्कारवान और सशक्त समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में 11 अक्टूबर को शासकीय आईटीआई कॉलेज पंचौर बैटन में नशामुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के माध्यम से युवाओं एवं समाज के लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा समाज में स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना



रहा। आयोजकों ने नशामुक्त समाज की आवश्यकता पर बल देते हुए युवाओं को अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। आज के दौर में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाली गंभीर चुनौती है। ऐसे में नशामुक्ति

के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से आयोजित इस अभियान ने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनमें विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री बृजेश जायसवाल, जिला सहसंयोजक राजबली साह, जिला सह संयोजक ध्रुव सोनी तथा बजरंग दल के सिंगरौली प्रखंड संयोजक शिवम शर्मा शामिल रहे।

राजीव चौक से इंदिरा चौक तक सड़क निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

सिंगरौली। शहर के प्रमुख मार्ग राजीव चौक से इंदिरा चौक तक सड़क निर्माण का काम आखिरकार दोबारा शुरू हो गया है। बरसात के कारण निर्माण कार्य रोकना पड़ा था,जिससे सड़क निर्माण को लेकर इंतजार कर रहे शहरवासियों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मौसम अनुकूल होने के बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू होने से परियोजना की गति मिलने की संभावना है। इसी क्रम में नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम अध्यक्ष ने मौके पर चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति देखी तथा कार्य से संबंधित जानकारी ली। राजीव चौक से

नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने किया निरीक्षण



इंदिरा चौक तक का मार्ग शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है। इस सड़क से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़क निर्माण पूरा होने के बाद यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने

सड़क निर्माण का काम शुरू होने के बाद बरसात के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो गई थी। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते निर्माण कार्य बंद करना पड़ा था। बारिश के दौरान सड़क निर्माण प्रभावित होने से परियोजना की गति धीमी हो गई थी। अब मौसम में सुधार के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में काम में तेजी आएगी और सड़क निर्माण को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

शहरवासियों को बेहतर

सड़क का इंतजार

राजीव चौक से इंदिरा चौक तक सड़क का निर्माण शहर की

यातायात व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मार्ग के बेहतर होने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब नागरिकों की निगाहें इसके समय पर पूरा होने पर टिकी हैं। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के निरीक्षण के बाद निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि सड़क निर्माण कब तक पूरा होगा, इसकी समय-सीमा के संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में शहरवासियों को उम्मीद है कि संबंधित एजेंसी निर्माण कार्य को गति देते हुए गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करेगी ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा का लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में सीधी जिले को राष्ट्रीय सम्मान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदान की ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र

फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाने के उत्कृष्ट कार्यों को मिली राष्ट्रीय पहचान

सीधी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सीधी जिले को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। जिले को यह सम्मान फसल कटाई के उपरांत भंडारण क्षमता में वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर उप संचालक कृषि आर.एस. गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र शैलेन्द्र गौतम, अनुविभागीय कृषि अधिकारी अंकिता तिवारी तथा प्रगतिशील कृषक विपिन शुक्ला उपस्थित रहे। यह सम्मान जिले में कृषि विकास, कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत देश के 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने



तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। सीधी जिला भी इस योजना के अंतर्गत चयनित है। योजना के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय कर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत जिले में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण, कृषि ऋण की उपलब्धता बेहतर बनाने तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन,

मत्स्यपालन एवं अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। फसल कटाई के बाद कृषि उपज का सुरक्षित भंडारण किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर भंडारण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर विकसित करने तथा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग के साथ पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सिंचाई एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं के अभिसरण पर जोर दिया जा रहा है। कृषि

उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग, किसान प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि ऋण की उपलब्धता तथा कृषि उपज के बेहतर प्रबंधन जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही दलहन, तिलहन एवं श्रीअन्न जैसी फसलों के प्रोत्साहन, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य जिले की कृषि क्षमता का बेहतर उपयोग करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सीधी जिले को प्राप्त राष्ट्रीय सम्मान कृषि विकास एवं कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा सम्मान प्राप्त किया जाना जिले के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, संबंधित विभागों और किसानों के समन्वित प्रयासों को नई प्रेरणा प्रदान करेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों का भविष्य होगा आर्थिक रूप से सुरक्षित

सीधी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण बचत योजना है। इस योजना का उद्देश्य 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को प्रोत्साहित करते हुए अभिभावकों को बेटियों के भविष्य के लिए नियमित बचत करने के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत डाकघर में पात्र बेटी के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। इसमें न्यूनतम 250 रुपये

10 वर्ष से कम आयु की बेटी के नाम पर खुलवा सकते हैं खाता, बचत पर मिलता है आकर्षक ब्याज और आयकर में छूट

तथा अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष जमा किए जा सकते हैं। योजना की ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान ब्याज दर की पुष्टि संबंधित डाकघर से की जा सकती है। इस योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के

मेहनत, बचत और हौसले से बदली जिंदगी, शांति साकेत बनी 'लखपति दीदी'

सीधी। कभी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाली जिले के मझौली विकासखंड के ग्राम दादर की शांति साकेत आज अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर आत्मनिर्भरता की नई पहचान बना चुकी हैं। अनुसूचित जाति परिवार से आने वाली शांति साकेत ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की।

एकलव्य स्कूल हड़बड़ो के 3 छात्र-छात्राओं का संभाग स्तर में चयन

सीधी। सीधी जिले के एकलव्य पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, हड़बड़ो के प्रतिभावान छात्र- छात्राओं ने कबड्डी एवं बास्केटबॉल बॉल में शाहदार प्रदर्शन करते हुए संभाग में अपनी जगह बनायी है। खनक पाण्डेय बास्केटबॉल एवं अतुल सिंह और यशधीर सिंह ने कबड्डी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुये एक बार फिर स्कूल और पूरे जिले का नाम रोशन किया है। 70वां शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत बीते 10 अक्टूबर को सीधी में आयोजित जिला स्तरीय (17 वर्ष)



प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अपने शानदार खेल कौशल की बढौलत तीनों छात्रों का चयन सीधे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जहाँ दिनांक 13 अक्टूबर को ये रीवा में अपनी खेल कौशल से राज्य स्तर पर चयनित होने की दावेदारी करेंगे।

यह स्कूल न केवल पढ़ाई बल्कि अन्य रचनात्मक गतिविधियों में हमेशा जिले में प्रथम स्थान पर रहता है। सांस्कृतिक, बॉक्सिंग, कुश्ती वॉलीबॉल, खो-खो, क्रिकेट, वुशू जैसी स्पर्धाओं में भी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता आ रहा है। इसी कड़ी में अब विद्यालय की सभी टीम ने अपनी मजबूत दावेदारी से सबको प्रभावित किया है। संभाग स्तर पर चयन होने से एकलव्य स्कूल हड़बड़ो के खेल शिक्षक अरविन्द सिंह, रजनीश पाण्डेय, सौरभ केवट एवं उनके

माता पिता तथा समस्त स्टाफ में भारी हर्ष का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत यह मुकाम हासिल किया है। सीधी में आयोजित इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी ने जिले का मान बढ़ाया है। इस सम्भाग स्तर की प्रतियोगिता रीवा में 12 एवं 13 अक्टूबर को आयोजित होगी। और वहां से चयनित छात्र राज्य स्तर पर अपनी खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

संभाग स्तरीय कराते प्रतियोगिता के लिए गणेश स्कूल के 29 खिलाड़ियों का हुआ चयन

सीधी। जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर एसजीएसएस स्कूल, पड़रा और श्री गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल, अमहा के कुल 29 खिलाड़ियों का चयन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 परिसर में आयोजित की गई थी। चयनित खिलाड़ियों में एसजीएसएस स्कूल, पड़रा के 22 तथा श्री गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल, अमहा के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 13 अक्टूबर को सतना में किया जाएगा। प्रवक्ता राजकपूर चितेरा ने बताया कि एसजीएसएस स्कूल, पड़रा से सीभाग पाण्डेय, तरुण तिवारी, आयुष शुक्ला, निशि

त्रिपाठी, अनुषा द्विवेदी, शुभो दीपाली गुप्ता, कत्यानी द्विवेदी, आस्था सिंह, अर्पिता तिवारी, आदित्य सिंह, यशराज सिंह, कार्तिका तिवारी, अपूर्वा सिंह, समृद्धि सिंह, सुभांगी सिंह, कैरिश गुप्ता, शिवानंद तिवारी, अथर्व सिंह, उदित प्रताप सिंह, संस्कृत उपाध्याय, आद्या प्रधान एवं अंकिता शुक्ला का चयन हुआ है। वहीं, श्री गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल, अमहा से सूर्यश गुप्ता, सुभांशु पटेल, सौरभ पटेल, शिवम् पटेल, अभिनव मिश्रा, रौनक तिवारी एवं कृष्णन्दु साहू ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। श्री गणेश ग्रुप के एकेडमिक डायरेक्टर एवं प्राचार्य डॉ. महेंद्र कुमार तिवारी ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते

हुए कहा कि यह सफलता उनके अनुशासन, निरंतर अभ्यास और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का भी विकास करते हैं। डॉ. तिवारी ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए विधास जताया कि वे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन करेंगे। विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर एच.एम. माएमा सिमन्स, प्राइमरी कोऑर्डिनेटर रेखा शर्मा, खेल प्रशिक्षक तरुणनाथ मिश्र, सूरज शुक्ल, सुभाष शुक्ल, माखनलाल मिश्र, विश्वास पाण्डेय, प्रियंका सिंह एवं अंकुर मिश्र सहित समस्त स्टाफ ने प्रसन्नता व्यक्त की।

मोबाइल मेडिकल यूनिट खाना, बैगा जनजातीय परिवारों को घर के पास मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा

सांसद ने हरी झंडी दिखाकर कुसमी के लिए किया खाना, सेवा संकल्प अभियान के तहत अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर

सीधी। जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी के सुदूर अंचलों में निवासरत बैगा जनजातीय समुदाय सहित अन्य ग्रामीण परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की गई है। सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने राजस्थान से प्राप्त अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर कुसमी विकासखंड के लिए खाना किया। इस यूनिट के माध्यम से दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य जांच, उपचार और आवश्यक दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर देव कुमार सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे, जिला चिकित्सालय के चिकित्सकगण तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट का स्टाफ उपस्थित रहा। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने यूनिट में उपलब्ध चिकित्सकीय उपकरणों, आवश्यक दवाइयों एवं



अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों का निरीक्षण किया और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिले में संचालित सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन इसी भावना के अनुरूप दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विशेष रूप से उन परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें दूरी, आवागमन की कठिनाइयां अथवा अन्य कारणों से अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किसी भी परिवार को केवल दूरी या संसाधनों की कमी के कारण उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जनकल्याण और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न पहल की जा रही हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि बैगा जनजातीय समुदाय सहित जरूरतमंद परिवारों को समय पर जांच, उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। यूनिट का संचालन नियमित और प्रभावी ढंग से किया जाए, ताकि इसका वास्तविक लाभ ग्रामीणों को मिल सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से कुसमी विकासखंड के दूरस्थ ग्रामों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर जांच, उपचार एवं दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए सीधी का दल रीवा खाना

जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को किया खाना

सीधी। संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए सीधी जिले के खिलाड़ियों के दल को जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रीवा के लिए खाना किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रीवा में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में सीधी जिले के खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के



माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने तथा संभाग स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। जिला शिक्षा

अधिकारी पवन कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना, अनुशासन और समर्पण के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने को अपेक्षा व्यक्त की। सीधी जिले के खेल दल के रीवा खाना होने पर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल रहा। जिलेवासियों को उम्मीद है कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित करेंगे।

जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां शुरू, सीधी में जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ

जनगणना कार्य की तैयारियों को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्राप्त किया प्रशिक्षण

सीधी। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के तहत सीधी जिले में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज 12 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, जनगणना लिपिकों, तकनीकी सहायकों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। जनगणना कार्य निदेशालय, भोपाल से आए प्रशिक्षक सुमित मौर्य एवं वैभव



अग्रवाल ने अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय के निर्देशन में प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 60 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता करते हुए जनगणना से संबंधित प्रक्रियाओं एवं दायित्वों की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनगणना

2027 के द्वितीय चरण के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रक्रियाओं, कार्ययोजना तथा जिम्मेदारियों से अवगत कराना है, ताकि जनगणना का कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण के माध्यम से जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

संजय टाइगर रिजर्व की पहल से बेरोजगारी से रोजगार की ओर बढ़े 33 युवा

8 वन ग्रामों के युवाओं को एलएंडटी में प्रशिक्षण का अवसर, दो माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद रोजगार की सुविधा

सीधी। संजय टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा वन क्षेत्रों से लगे दूरस्थ ग्रामों के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की अभिनव पहल की गई है। इस पहल के तहत आठ वन ग्रामों के 33 युवाओं को एलएंडटी कंपनी के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, लखनादौन (जिला सिवनी) के लिए खाना किया गया। चयनित युवाओं को दो माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उन्हें कंपनी की देशभर में स्थित इकाइयों में रोजगार उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा। संजय टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं ईको विकास समितियों के



संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए 5, 6 एवं 7 अक्टूबर 2026 को विभिन्न वन ग्रामों में विशेष काउंसिलिंग शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में एलएंडटी कंपनी, लखनादौन के कौशल विकास केंद्र के प्रभारी कमल चंद्रवंशी ने युवाओं को

एवं रोहल ग्रामों के कुल 33 युवाओं का चयन किया गया है। इन युवाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है। इनमें ऐसे युवा भी शामिल हैं, जिन्होंने आठवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी और आर्थिक परिस्थितियों के कारण मजदूरी करने को मजबूर थे। कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से इन युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक दक्षताएं हासिल करने का अवसर मिलेगा। इससे वे अपने भविष्य के लिए बेहतर विकल्प तलाश सकेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकेंगे। चयनित युवाओं को एलएंडटी के लखनादौन स्थित

कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में दो माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी द्वारा रहने और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को कंपनी की देशभर में स्थित इकाइयों में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यह पहल उन ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष महत्व रखती है, जिन्हें सीमित शैक्षणिक अवसरों और आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने में परेशानी होती है। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें अपने कौशल को विकसित करने और रोजगार के व्यापक अवसरों तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी।

सीएम हेल्पलाइन की 50 दिवस से ऊपर की शिकायतों पर करें फोकस

100 दिवस से अधिक और नाट-अटेण्ड नहीं रहनी चाहिए शिकायतें, समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर के निर्देश

सतना। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में सभी विभाग प्रमुख अधिकारी 50 दिवस से ऊपर की शिकायतों पर फोकस करें। किसी भी विभाग में 100 दिवस तक अनावश्यक रूप से शिकायतें लंबित नहीं रहनी चाहिए और ना ही किसी स्तर पर कोई शिकायत नाट-अटेण्ड होनी चाहिए। सोमवार को कलेक्टर ने समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के 100 दिवस से ऊपर के लंबित प्रकरणों में विभागवार समीक्षा की। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम डॉ. नागार्जुन भी गौड़ा, सीईओ जिला पंचायत सपना त्रिपाठी, अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम राहुल सिलाडिया, डिप्टी कलेक्टर जितेंद्र वर्मा, सदीप परस्ते सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सोमवार को बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण, रेलवे के समन्वय के मुद्दों पर भी समीक्षा की। एनएचपीडब्ल्यूडी द्वारा रीवा-सतना सड़क पर रोड रेस्टोरेशन मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं प्रारंभ किए जाने पर संबंधित विभाग प्रमुख को पत्र लिखने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सतना-चित्रकूट मार्ग पर सड़क मरम्तीकरण का कार्य कोटी बाईपास में अब तक प्रारंभ नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की दीपावली मेला के पहले संपूर्ण सड़क दुरुस्त हो जानी चाहिए। इसके लिए कोटी बायपास, मझगांव बायपास और घाट एरिया में कुल तीन टीमें अलग-अलग लगाएँ। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और आतिशबाजी पटाखा दुकानों के संबंध में भी कलेक्टर ने तत्काल कार्यवाहियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में नारायण तालाब के पास आतिशबाजी पटाखा की दुकान लगाई जाएगी। स्थल का निरीक्षण और आवश्यक तैयारियां अभी से शुरू करें। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के पीछे और नारायण तालाब के पास दशहरा पर होने वाले रावण दहन के लिए भी सुरक्षात्मक आवश्यक तैयारियां प्रारंभ करें।

सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि ग्रेडिंग के लिए अभी 8 दिन का समय है। अधिकाधिक शिकायतों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण करें तथा जो शिकायतें विधिवत रूप से संतुष्टि पूर्ण बंद नहीं की जा सकती। उसके लिए सकारण टिप्पणी के साथ क्लोजर के लिए प्रस्तावित कराएँ। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख अपनी 50 दिवस की शिकायतों पर फोकस कर निराकरण करें ताकि 100 दिवस तक लंबित नहीं रहे। भुगतान संबंधी शिकायतों के क्लोजर प्रस्ताव में अवेदक को भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि भी की जानी चाहिए। ऊर्जा विभाग के बरहरना वितरण केंद्र में अधिक संख्या में शिकायतों के लंबित रहने पर संबंधित जेई को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सहकारिता विभाग में निराकरण उचित नहीं होने पर संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

हिट एंड रन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराएं: कलेक्टर

पीएम राहत, रोड सेफ्टी, जीरो फैटलिटी की समीक्षा बैठक

सतना। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि हिट एंड रन के शेष बचे प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के राहत प्रकरणों में भी कोई भी प्रकरण 60 दिवस से अधिक समय तक भुगतान के लिए लंबित नहीं रहने चाहिए। पीएम राहत, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट और हिट एंड रन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, डीएफओ मयंक चांदीवाल, आयुक्त नगर निगम डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा, सीईओ जिला पंचायत सपना त्रिपाठी, अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम राहुल सिलाडिया, डिप्टी कलेक्टर सदीप परस्ते भी उपस्थित थे।

रोड सेफ्टी की बैठक में बताया गया कि चिन्हांकित 150 लोकेशन पर ट्रैफिक और आरटीओ तथा सड़क एजेंसी के अधिकारियों को ज्वाइंट विजिट करना है। जिनमें 21 लोकेशन लोक निर्माण विभाग के हैं, जबकि 127 लोकेशन पर संकेतक लगाए जाने की कार्यवाही की जानी है।

पीएम राहत योजना में बताया गया कि सतना जिले के सभी शासकीय और निजी चिकित्सा संस्थाएं योजना में रजिस्टर्ड कर ली गई हैं। अब तक दुर्घटनाग्रस्त लोगों के इलाज खर्च के लिए कुल 154 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिनमें 135 प्रकरणों में स्वीकृति दी जा चुकी है। सतना जिले में कुल 54 चिकित्सा संस्थाएं योजना में रजिस्टर्ड की गई हैं।

वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण, संवाद कार्यक्रम आयोजित

सेवा मेरा योगदान एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत वरिष्ठजनों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति किया गया जागरूक

सतना। अटल बयो अभ्युदय योजना एवं सेवा मेरा योगदान अभियान (सेवा संकल्प अभियान 2026) के अंतर्गत जिले के विभिन्न वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवेदनशीलता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उनसे आत्मीय संवाद कर उनके स्वास्थ्य, सुविधाओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली गई। जिले के वृद्धाश्रमों में आयोजित इन

कार्यक्रमों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करना, उनके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करना तथा उन्हें स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना रहा। इस दौरान आयुष विभाग के विशेषज्ञों एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिक उपचार, आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानियों, पोषण, सामान्य रोगों से बचाव, स्वस्थ जीवनशैली और योगाभ्यास के संबंध में व्यवहारिक जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमोदवन वृद्धाश्रम चित्रकूट, डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चौरिटेबल ट्रस्ट वृद्धाश्रम चन्द्राश्रम नीमी-सकरिया, दुर्गा वृद्ध सेवा समिति वृद्धाश्रम सरभंगा, मांडल शिक्षा समिति वृद्धाश्रम सोनौरा, प्रभा श्री जन कल्याण समिति वृद्धाश्रम श्यामनगर तथा प्रशासक श्री शांदा प्रबंधक वृद्धाश्रम मेहर सहित जिले के विभिन्न वृद्धाश्रमों में गतिविधियां आयोजित की गईं।

स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल, सोहावल में मसाला वितरण केंद्र का शुभारंभ

मध्यान्ह भोजन योजना एवं शासकीय कर्मचारियों तक गुणवत्तापूर्ण मसालों की आपूर्ति का लक्ष्य

एनआरएलएम से जुड़े समूहों को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

सतना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। कमिश्नर रीवा संभाग श्री शीलेन्द्र सिंह के निर्देशन में संभाग के समस्त विकासखंडों में एनआरएलएम से गठित स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मसाला यूनिट स्थापित कर उन्हें मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम)

उत्पादों के लिए नियमित बाजार तैयार करना तथा समूहों की आय में वृद्धि करना है। मसाला यूनिटों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मसालों का उत्पादन, पैकेजिंग एवं वितरण कर महिलाओं को आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। योजना के तहत स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार मसालों को मध्यान्ह भोजन योजना से जोड़ने तथा जिले के शासकीय कर्मचारियों तक उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है। इससे समूहों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक व्यवस्थित माध्यम प्राप्त हो सकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह पहल महिला सशक्तीकरण, स्थानीय

उद्यमिता एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एनआरएलएम के माध्यम से गठित स्व-सहायता समूहों की क्षमता का उपयोग करते हुए उन्हें उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले से सहायक जिला प्रबंधक कुशलेन्द्र सिंह, प्रभारी जिला प्रबंधक लघु उद्यमिता विकास सतेन्द्र सिंह, जनपद पंचायत से विकासखण्ड प्रबंधक श्वेता सिंह, सहायक विकासखण्ड प्रबंधक सीमा द्विवेदी, पूर्णमा मिश्रा, कंचन त्रिपाठी, करुणा पाण्डेय, विनय शर्मा एवं जनपद के एडीओ, पीसीओ एवं समस्त कर्मचारी सम्मिलित रहे।

किताबों से निकलकर प्रकृति की पाठशाला पहुंचे विद्यार्थी, दूरबीन से देखी पक्षियों की दुनिया

दक्षिण पन्ना की रैपुरा रेंज में अनूठा जागरूकता कार्यक्रम, चार विद्यालयों के 30 विद्यार्थियों ने सीखी पक्षियों की पहचान, जाना वन्यजीव संरक्षण का महत्व और वन सेवाओं में करियर के अवसर

पन्ना। वन्यजीव सप्ताह के क्रम में दक्षिण पन्ना वनमंडल के रैपुरा वन परिक्षेत्र में रविवार को पक्षी अवलोकन एवं वन्यजीव जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आसपास के चार विद्यालयों के 30 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति एवं वन्यजीवों से जोड़ने के साथ-साथ उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों को दूरबीन के उपयोग एवं पक्षियों की पहचान की जानकारी देने से हुई। इसके बाद भारतीय वन सेवा के अधिकारी एवं प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी रैपुरा कृष्ण प्रसाद बी., प्रकृतिविद अजय चौरसिया तथा वनरक्षक वीरेंद्र पटेल, सतीश द्विवेदी एवं रजनीश चौदेरिया के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने निकटवर्ती तालाब पर पक्षी अवलोकन किया। इस दौरान बच्चों ने दूरबीन से टिटहरी, पतरिंगा (बी-ईटर), चित्रित सारस (पेंटेड स्टार्क), अबाबील, चितकवरी फाख्ता, कोतवाल (डोंगो) और नीलकंठ सहित विभिन्न पक्षियों को देखा तथा उनकी पहचान और विशेषताओं के बारे में जाना। इसके पश्चात आयोजित जागरूकता सत्र में विद्यार्थियों को

मध्यप्रदेश की समृद्ध वन्यजीव विविधता, पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की सफल पुनर्स्थापना तथा देश में चीता पुनर्स्थापन परियोजना के बारे में रोचक जानकारी दी गई। बच्चों को समझाया गया कि वन्यजीव केवल जंगलों की शोभा नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन, नदियों एवं जलस्रोतों के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता तथा खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर आयोजित वन्यजीव आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में श्री रामकृष्ण पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, रैपुरा की टीम विजेता रही। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण विद्यार्थियों के लिए आयोजित करियर मार्गदर्शन सत्र रहा। इसमें बच्चों को भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वन्यजीव अनुसंधान एवं पशु चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध करियर के

अवसरों से परिचित कराया गया। इस दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को वन परिक्षेत्र अधिकारी की कुर्सी पर बैठने का अवसर दिया गया, ताकि वे वन अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने के साथ भविष्य में ऐसी सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित हो सकें। बच्चों ने वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान देने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को स्मृति स्वरूप पौधे भेंट किए गए तथा उन्हें पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान से आगे बढ़कर प्रकृति को प्रत्यक्ष देखने, समझने और उससे जुड़ने का अवसर मिला। अंत में सामूहिक छायाचित्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

पन्ना की 21 बेटियों को मिला रोजगार, 4 और का अपोलो भोपाल में प्लेसमेंट

ग्रीन इंडिया मिशन के तहत दक्षिण पन्ना वनमंडल की कौशल विकास पहल के सकारात्मक परिणाम, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे रोजगार के अवसर

पन्ना। दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के आजीविका एवं कौशल विकास घटक के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से रोजगार के सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ दिनों पूर्व चार और प्रशिक्षार्थियों का अपोलो सेज हॉस्पिटल, भोपाल में सफलतापूर्वक प्लेसमेंट हुआ। इसके साथ ही जनरल ड्यूटी असिस्टेंट प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालों में रोजगार पाने वाली बेटियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है।

शाहनगर में आयोजित त्त्र प्रशिक्षण के माध्यम से युवतियों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आवश्यक व्यावहारिक एवं व्यावसायिक कौशल प्रदान किए गए। प्रशिक्षण के बाद अब तक प्रशिक्षार्थियों का अपोलो सेज हॉस्पिटल, भोपाल, मेदांता हॉस्पिटल, इंदौर तथा शाल्बी हॉस्पिटल, जबलपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयन एवं प्लेसमेंट हुआ है। कई प्रशिक्षार्थियों के लिए यह उनकी पहली नियमित नौकरी है और कुछ बेटियां अपने परिवार की प्रमुख अथवा एकमात्र आय अर्जित करने वाली सदस्य भी बनी हैं।

दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत केवल सीडीए ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर, आईटी, सिलाई, ब्यूटी

एवं वेलनेस, वाहन मरम्मत, मोबाइल हार्डवेयर, वेब डेवलपमेंट, शेफ एवं लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न कौशल प्रशिक्षण भी पर्व, शाहनगर, मोहनदा और सलेहा क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आयवर्धन के बेहतर अवसरों से जोड़ना है।

वन संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। 21 बेटियों का प्रतिष्ठित अस्पतालों में चयन और प्लेसमेंट न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर पन्ना के ग्रामीण अंचलों की बेटियां आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकती हैं।

वनकर्मियों के मानवीय प्रयास से सर्पदंश पीड़ित आदिवासी ग्रामीण को समय पर मिला उपचार

इस मानवीय पहल में वनपाल प्रेम नारायण वर्मा, महेश पटेल एवं सुरक्षा श्रमिक केशव प्रसाद दहायत ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रेम नारायण वर्मा ने पीड़ित परिवार को व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की। दक्षिण पन्ना वनमंडल ने नागरिकों से अपील की है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़ू-फूंक अथवा घरेलू उपचार में समय न गंवाएं, बल्कि पीड़ित को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएं। समय पर चिकित्सकीय उपचार और आवश्यकता के अनुसार एंटीवेनम का उपयोग सर्पदंश से होने वाली मृत्यु एवं गंभीर जटिलताओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पीड़ित झाड़ू-फूंक से ठीक होने की धारणा के कारण अस्पताल जाने को तैयार नहीं था। वनकर्मियों ने उसे एवं उसके परिजनों को समझाइश देकर चिकित्सकीय उपचार के लिए राजी किया तथा वाहन की व्यवस्था कर परिवार सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शाहनगर पहुंचाया।

छह वनकर्मियों ने खोले सर्पदंश के रहस्य, दक्षिण पन्ना में 1,261 घटनाओं का विस्तृत अध्ययन

चौंकाने वाले निष्कर्ष: 67% सर्पदंश पीड़ितों ने पहले झाड़ू-फूंक का सहारा लिया, आधे से अधिक मौतें नौद के दौरान हुए सर्पदंश से, बच्चों की सुरक्षा और समय पर उपचार पर विशेष जोर

पन्ना। दक्षिण पन्ना वनमंडल के छह मैदानी वनकर्मियों द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन बियांड द बाइट अंडरस्टैंडिंग स्नेकबाइट, सेविंग लाइव्स ने सर्पदंश से जुड़े कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। वनमंडल के छह परिक्षेत्रों के लगभग 280 गांवों में सर्पदंश की 1,261 घटनाओं का अध्ययन किया गया, जिनमें 1,065 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हुए, 34 व्यक्ति स्थायी शारीरिक समस्याओं के

साथ जीवित रहे, जबकि 162 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई। विशेष बात यह है कि यह अध्ययन किसी बाहरी शोध संस्था के बजाय वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों एवं पीड़ित परिवारों से सीधे संवाद करके तैयार किया गया है। अध्ययन में घटनास्थल, समय, गतिविधि, सर्प की प्रजाति, उपचार, अस्पताल की दूरी, घरेलू परिस्थितियों तथा अन्य कारकों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि सर्पदंश से होने वाली मौतों का बड़ा हिस्सा रात और नौद के दौरान हुई घटनाओं से जुड़ा है। कुल 162 मौतों में से 84 मौतें (लगभग 52 प्रतिशत) के सोते समय सर्पदंश के कारण दर्ज की गईं, जबकि 97 मौतें घर के कमरों में हुई घटनाओं से संबंधित थीं। बच्चों से जुड़े आंकड़े विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। अध्ययन में 14 वर्ष तक के 73 बच्चों में से 32 की मृत्यु दर्ज हुई, जबकि नौद के दौरान सर्पदंश का शिकार हुए 25 बच्चों में से 20 की मृत्यु हुई। इनमें करीब जैसी सर्पों की भूमिका महत्वपूर्ण पाई गई, जिनका दंश कई बार अत्यंत कम दर्द वाला होता है और सोते समय उसका पता भी नहीं चल पाता। ये आंकड़े सर्वेक्षण में शामिल घटनाओं से संबंधित हैं,

इन्हें पूरे जिले की मृत्यु दर नहीं माना जाना चाहिए। समय पर अस्पताल पहुंचना जीवनरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक पाया गया। सर्वेक्षण में 840 पीड़ित (लगभग 67 प्रतिशत) उपचार के लिए सबसे पहले पारंपरिक झाड़ू-फूंक अथवा वैद्य के पास गए। ऐसे मामलों में अस्पताल पहुंचने का मध्यक समय तीन घंटे रहा, जबकि सीधे अस्पताल जाने वालों में यह एक घंटा था। जिन गंभीर विषैले सर्पों से संबंधित घटनाओं में अस्पताल पहुंचने का समय दर्ज था, उनमें एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचे पीड़ितों में मृत्यु का अनुपात 12.9 प्रतिशत, जबकि चार घंटे से अधिक समय बाद पहुंचने वालों में 46.2 प्रतिशत पाया गया। यह अंतर शीघ्र उपचार के महत्व को रेखांकित करता है।



कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय की अध्यक्षता में उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति, लंबित प्रकरणों के प्राथमिकता से निराकरण तथा बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।



सीएम हेल्पलाइन में सौ दिन से अधिक की सभी शिकायतें निराकृत करें : कलेक्टर

रीवा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण करें। कई बार निर्देश के बावजूद इनके निराकरण के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस सप्ताह अच्छा प्रयास करके बड़ी संख्या में आवेदनों का निराकरण किया है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग तथा ऊर्जा विभाग को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन और 100 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों के कारण जिले की रैंकिंग में गिरावट आती है। मांग आधारित सभी शिकायतों को बंद



कराएं। बजट आवंटन, भुगतान और नीतिगत मामलों से संबंधित आवेदन पत्रों को कलेक्टर के अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से विभाग प्रमुख को प्रेषित करें। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में लंबित आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति सहन नहीं की जाएगी। इन दोनों विभागों के लंबित प्रकरणों की 14 अक्टूबर को समीक्षा की जाएगी। सभी एसडीएम सामान्य प्रशासन विभाग तथा भू-अर्जन से संबंधित आवेदनों का तत्परता से निराकरण कराएं। त्योंथर, जवा और मनगवां एसडीएम इस पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने बैठक से बिना सूचना तथा अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को नोटिस देकर एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में दर्ज

प्रकरणों में समय पर जवाब-दावा दायर करें। अवमानना के प्रकरणों में तत्काल न्यायालय के निर्देशों का पालन करके पालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं की शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित विभागीय लक्ष्यों से 25 प्रतिशत अधिक स्वरोजगार प्रकरण बैंकों में 20 अक्टूबर तक दर्ज करा दें। इन प्रकरणों को बैंकों से नियमित संपर्क करके 30 अक्टूबर तक ऋण स्वीकृत तथा वितरित कराएं। जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक में इसकी विभागवार तथा बैंकवार समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी झण्डा दिवस की सहयोग राशि एक सप्ताह में जमा करा दें। सैनिक कल्याण कोष में

धुमंतू तथा अर्द्धधुमंतू के जाति प्रमाण पत्र के लिए लगंगे शिविर

रीवा। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त धुमंतू तथा अर्द्धधुमंतू समुदाय के सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के लिए प्रभारी अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि 15 अक्टूबर को त्योंथर तहसील परिसर में तथा 21 अक्टूबर को जवा तहसील में डभौरा नगर परिषद कार्यालय परिसर में शिविर लगेंगे। इसी तरह 22 अक्टूबर को हुजूर तहसील के गोविंदगढ़ नगर परिषद तथा 28 अक्टूबर को सेमरिया में तहसील परिसर में शिविर लगाए जाएंगे। सभी तहसीलदार तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मैदानी कार्यवाहियों के माध्यम से धुमंतू और अर्द्धधुमंतू परिवारों की बस्तियों और डेरों में जाकर शिविर की जानकारी दें।

रोजगार मेला टीआरएस कॉलेज में 14 अक्टूबर को

रीवा। युवा संगम कार्यक्रम के तहत शासकीय टीआरएस कॉलेज रीवा में 14 अक्टूबर को वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में रीवा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। रोजगार मेले में 24 शामिल हो रही हैं। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में आने वाले युवाओं का पंजीयन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। मेले में शामिल होने वाले युवाओं के लिए आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए युवाओं को आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए, समस्त ट्रेडों से आईटीआई उतीर्ण तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त युवा रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। वेतन एवं भत्ते 7 हजार रुपए से 35 हजार रुपए कंपनीवाइन अलग-अलग निर्धारित किया गया है। रोजगार मेले में आने वाले युवाओं को अपने साथ समग्र आईडी, मूल अंकसूची को छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र को छायाप्रति, आधार कार्ड या वोट

आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लाना अनिवार्य होगा। उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में यवाकी इंडिया प्रा. लि. अहमदाबाद, एमआरएफ लि. हैदराबाद, आपोलो टायर्स लि. बड़ोदरा गुजरात, आईड्यूआई पीथमपुर धार, आयसर टूक एण्ड बस पीथमपुर, ऑल इंडिया फिसस याई विवर वेलफेयर एसोसिएशन रीवा, प्रातिशील बायोटेक प्रा. लि. रीवा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड रीवा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलूर, न्यू जेल फैशन प्रा. लि. धार, मैं पावर ग्रुप इंडिया प्रा. लि. गुरुग्राम हरियाणा, हायर अल्ताएस्सेस इंडिया लि. पूर्ण, एस्कलेपिडस वेलनेस प्रा. लि. रीवा, प्रातिशील एगोटेक प्रा. लि. रीवा, हायली इंडिया प्रा. लि. हैदराबाद, एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रीवा, सीआईआई एससीसी पीथमपुर इंदौर, सीटी कार प्रा. लि. रीवा, प्रतिभा सॉल्यूट्स इंदौर म.प्र., बजाज लाइफ इश्योरेंस प्रा. लि. रीवा, यूगो मिंडा ईवो सिस्टम गुरुग्राम हरियाणा, प्रभा बायोल्जिक्स प्रा. लि. रीवा, शुभम इंटर प्राइजेज एण्ड एसोशिएट पीथमपुर तथा महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा इंदौर की कंपनियां शामिल हो रही हैं।

जल जीवन मिशन से आसान हुई तेरसी प्रजापति की जिंदगी

मऊगंज। मऊगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत कुलबहेरिया निवासी 60 वर्षीय श्रीमती तेरसी प्रजापति के लिए पहले पानी की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती थी। पेयजल की समस्या के कारण उन्हें कुएं से पानी लाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम में एकल ग्राम नलजल योजना के तहत उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण कर पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पेयजल पहुंचाया गया। अब श्रीमती तेरसी प्रजापति को घर में ही नल से पानी मिल रहा है। इससे उनकी परेशानी कम हुई है और घरेलू कार्यों के लिए समय की बचत होने लगी है।

संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहेंगे कार्यपालक दण्डाधिकारी, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश : कलेक्टर

नवरात्रि एवं दशहरा पर्व पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने मजिस्ट्रियल इयूटी निर्धारित

मऊगंज। शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारियों की मजिस्ट्रियल इयूटी निर्धारित की गई है। जारी आदेश के अनुसार, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन एवं दशहरा (विजयादशमी) पर्व के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों, पुलिस

चौकियों एवं पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों को तैनाती की गई है। अधिकारियों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में उपस्थित रहकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा संबंधित व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के तहत अनुविभागीय दण्डाधिकारी हनुमना राजेश मेहता को हनुमना अनुविभाग तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी मऊगंज श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी को मऊगंज अनुविभाग की व्यवस्थाओं का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की इयूटी मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, लौर, सीतापुर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों में लगाई गई है।

कमिशनर आज करेंगे टीएल पत्रों की समीक्षा

रीवा। रीवा संभाग के कमिशनर शीलेन्द्र सिंह 13 अक्टूबर को कमिशनर कार्यालय सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण, सेवा संकल्प अभियान, सड़कों के सुधार, पेंशन प्रकरणों के निराकरण तथा आगामी फसल के लिए खाद और बीज के भण्डारण तथा वितरण की समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों से अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

रीवा। जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू रहेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही

साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए भारतीय नागरिक संहिता की 2023 धारा 163 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है।

जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही

की जाएगी। हावैस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रॉपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हावैस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नहीं होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नहीं दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हावैस्टर के साथ स्ट्रॉपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट

जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने के स्थान पर इसको स्ट्रॉपर से भूसा बनाकर पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग करें। किसान यदि गेंहू के बाद अन्य कोई फसल लेना चाहता है तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से फसल की बोनी करें। इससे नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद के रूप में फसल के लिए पोषण का कार्य करेगी। नरवाई को बेलर, रैकर एवं चापर मशीन की सहायता से बंडल बनाकर औद्योगिक ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जहाँ आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है।

पॉलीहाउस में गुलाब की खेती से कमा रहे प्रतिवर्ष 10 से 11 लाख रुपये का मुनाफा

मऊगंज। मध्यप्रदेश शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संरक्षित खेती योजना का लाभ लेकर मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत रकरी के प्रगतिशील कृषक श्री नरेंद्र सिंह सेंगर गुलाब की खेती से प्रतिवर्ष 10 से 11 लाख रुपये का मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। श्री सेंगर ने विभागीय अनुदान से एक एकड़ क्षेत्र में पॉलीहाउस का निर्माण कर वैज्ञानिक तकनीक से गुलाब उत्पादन शुरू किया। संरक्षित खेती के माध्यम से वे गुणवत्तायुक्त गुलाब का उत्पादन कर रहे हैं। उनके द्वारा

उत्पादित गुलाब की आपूर्ति प्रयागराज एवं मिर्जापुर के बाजारों में की जाती है। आधुनिक तकनीक और बेहतर विपणन व्यवस्था ने गुलाब की खेती को उनके लिए लाभकारी व्यवसाय बनाया है। श्री नरेंद्र सिंह सेंगर बताते हैं कि उद्यानिकी विभाग की योजना से अनुदान प्राप्त कर पॉलीहाउस में गुलाब की खेती शुरू करना उनके लिए लाभकारी साबित हुआ है। इससे उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 10 से 11 लाख रुपये का मुनाफा मिल रहा है।

विभागीय योजनाओं का संबंधितों के लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करे : अपर कलेक्टर

मऊगंज। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय की अध्यक्षता में उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति, लंबित प्रकरणों के प्राथमिकता से निराकरण तथा बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उद्यानिकी विभाग की फल पौध रोपण, नवीन बगीचों की स्थापना, सब्जी-

मसाला एवं पुष्प क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती और ट्रिप सिंचाई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत आवेदनों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मत्स्य विभाग की मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना की 30 सितंबर 2026 तक की प्रगति तथा मुख्यमंत्री मछुआ मृद्धि योजना के अंतर्गत स्मार्ट फिश पॉलर निर्माण के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसके

अलावा केज कल्चर से मत्स्य पालन, केज निर्माण लागत, मत्स्य बीज संचयन और मछली आहार पर होने वाले व्यय से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। अपर कलेक्टर ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए पात्र किसानों, उद्यमियों एवं मछुआरों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक संचालक उद्यानिकी डॉ दीक्षा चौर सहित संबंधित विभागों को अधिकारी उपस्थित रहे।

कोदो उपार्जन के लिए 21 केन्द्रों में किसानों का पंजीयन 5 नवम्बर तक

रीवा। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत श्रीअन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर कोदो और कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए किसानों का पंजीयन 5 नवम्बर तक किया जा रहा है। पंजीयन के लिए जिले में 21 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि किसानों

के पंजीयन के लिए सेवा सहकारी समिति गुढ़, भुनागांव, डभौरा, सोहरवा, कटरा, बैकुण्ठपुर, सिरमौर, सेमरिया, भमरा तथा बीड़ा में सुविधा दी गई है। सेवा सहकारी समिति गुढ़, गंगेव, मनगवां, कदौला, रघुराजगढ़, ब्यौहरा, रायपुर कर्चुलियान, बांसा, बहुरीबांध, गोविंदगढ़ तथा कहरिया मण्डी रीवा में भी किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी, उप संचालक कृषि

तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक सभी केन्द्रों में किसानों के पंजीयन के लिए समुचित व्यवस्था करें। पंजीयन केन्द्रों में कम्प्यूटर आफरेटर, लैपटाप, प्रिंटर, आधार सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन तथा पंजीयन के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था करें जिससे पंजीयन में किसी भी तरह की परेशानी न हो। ग्राम पंचायत के माध्यम से किसानों को पंजीयन के संबंध में जानकारी दें।

एपीएस विश्वविद्यालय में एक माह की 'छहुर लोकनाट्य' कार्यशाला का समापन 15 अक्टूबर को

रीवा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के बघेली शोधपीठ विभाग के सहयोग से आयोजित एक माह की 'छहुर लोकनाट्य' कार्यशाला का समापन समारोह 15 अक्टूबर 2026 को विश्वविद्यालय के शंभुनाथ सभागार में आयोजित किया जाएगा। 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक आयोजित इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को लोकनाट्य की विधा, रंगमंचीय प्रस्तुतियों और अभिनय की विभिन्न बारीकियों से परिचित कराया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षण



सहयोग रंग उत्सव नाट्य समिति, रीवा द्वारा प्रदान किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने लोकसंस्कृति, लोकपरंपराओं और बघेली अंचल की सांस्कृतिक विरासत को रंगमंच के माध्यम से समझने तथा प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाटक का निर्देशन अंकित मिश्रा एवं शुभम पांडेय ने किया, जबकि सह-निर्देशन की जिम्मेदारी गौरव सिंह ने निभाई। कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने

अर्जित कौशल को मंच पर प्रस्तुत करने की तैयारी की है। समापन समारोह में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेंद्र कुमार कुरारिया, विभु सूरि तथा बघेली शोधपीठ विभाग निर्देशक अनुराग मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. मुकेश उपाध्याय, उपनिदेशक हैं, जबकि कार्यक्रम के निवेदक श्री सुदेश शर्मा, निदेशक हैं। यह आयोजन क्षेत्रीय लोकनाट्य परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

बांस से स्वरोजगार के लिए समन्वित प्रोजेक्ट बनाएं : देशमुख

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बांसशिल्प के विकास के लिए विचार मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सुष्टि देशमुख गौड़ा ने कहा कि रीवा जिले में प्राकृतिक रूप से बांस का अच्छा उत्पादन होता है। बांस इमारती लकड़ी का अच्छा विकल्प है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बांस का उपयोग बहुत लाभकारी है। बांस का एक बार रोपण करने के बाद केवल चार-पाँच साल तक ही देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके बाद नाममात्र की देखरेख में लगभग 40 सालों तक इससे बांस प्राप्त होता रहता है। बांस के सुंदर और



आकर्षक बर्तन तथा सजावटी सामान बनाकर हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। रीवा में बांसशिल्प के विकास और स्वरोजगार को लेकर समन्वित कार्ययोजना बनाएं। इसमें ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामोद्योग, पर्यटन विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम तथा वन विभाग को शामिल करें। बैठक में मुख्य

कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स इंडस्ट्री बांसशिल्पियों को प्रशिक्षण देने आवश्यक तकनीकी तथा मशीनों उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाएं। पूरे जिले में बांसशिल्पियों के सर्वेक्षण तथा बांस उत्पादन की जानकारी के लिए भी प्रयास आवश्यक है। स्वरोजगार के लिए जिले में

शुरुआत में एक क्लस्टर बनाकर इसे प्रमोट किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए भवन तथा इसमें रूचि रखने वाले स्वरोजगारियों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सभी आयामों को शामिल करें, जिससे बांसशिल्पियों को आर्थिक विकास का अवसर मिलने के साथ बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन हो। बैठक में दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरैथिया ने बताया कि हरदा जिले में बांस बर्तन और सजावटी सामग्री बनाने का प्रोजेक्टर सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें 1200 से अधिक स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनों देकर जोड़ा गया

है। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भी बांसशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहा है। रीवा जिला में एक जिला-एक उत्पाद में भी बांस शामिल है। रीवा जिले में बांसशिल्पियों का सर्वेक्षण करके प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। हमारा संस्थान प्रशिक्षण तथा विपणन में सहयोग करेगा। रीवा ही नहीं संभाग के सभी जिलों में बांसशिल्प के विकास का अच्छा स्कोप है। बांस से बनी सामग्री मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ अन्य उत्पादों की तुलना में सस्ती भी है। बैठक में बांस के माध्यम से स्वरोजगार के विकास, प्रशिक्षण तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के संबंध में चर्चा की गई।